पेज थ्री देहरादून

हमारा दून

देहरादून बृहस्पतिवार 16 जुलाई 2020 पेज 8

दून में तेज बारिश से मकान के ऊपर गिरा पुश्ता। राहत कार्य में लगे कर्मी।

संक्षिप्त समाचार

हरेला पर्व होने से मानव अधिकार आयोग का कार्यालय में रहेगा अवकाश

संवाददाता देहरादून। अनु सचिव, उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग अखिलेश मिश्रा ने बताया कि उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग सहस्त्रधारा रोड, दून में दिनांक 16 जुलाई 2020 को हरेला पर्व का सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के फलस्वरूप कार्यालय में अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि उक्त तिथि दिनांक 16 जुलाई 2020 को निर्धारित परिवादों की सुनवाई अगले कार्य दिवस दिनांक 17 जुलाई, 2020 को निर्धारित की गयी है।

बेहतर अंक हासिल करने वाले छात्रों को सम्मानित करेगा उपंमा

संवाददाता देहरादून। उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक को जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं पंजाबी महासभा बेहतर अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करेगा। यहां जारी एक बयान में उत्तरांचल पंजाबी महासभा के गढ़वाल प्रभारी जी एस आनंद ने केन्द्रय मंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक को जन्मदिन पर बधाई व शुभकामनायें दी है और दूसरी और बच्चे बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक से पास हुए हैं उपमा की तरफ से सिल्वर स्टूडेंट, गोल्ड स्टूडेंट और पलेटीनम स्टूडेंट् जी अवॉर्ड दिए जाएंगे।

राज्य के सीमांत जनपदों को दिया जाये आर्थिक पैकेज

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड राज्य मे सामरिक दृष्टिकोण से सीमांत जनपदों के विकास के लिये आर्थिक पैकेज दिये जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। महानगर अध्यक्ष सुनील ध्यानी ने नेतृत्व में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करते हुए शीघ्र ही पैकेज प्रदान किये जाने की मांग की है।

फोर्ड इंडिया ने ईकोस्पोर्ट का नया ऑटोमैटिक वैरिएंट लॉन्च किया

संवाददाता देहरादून। ग्राहकों को ज्यादा विकल्प एवं बेहतर उपयोगिता प्रदान करते हुए फोर्ड इंडिया ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी ईकोस्पोर्ट का नया ऑटोमैटिक वैरिएंट विशेष मूल्य 10.66 लाख रु. (एक्सशोरूम दिल्ली) में प्रस्तुत किया है। नई फोर्ड ईकोस्पोर्ट टाईटेनियम ए.टी ट्रिम फोर्ड के लेटेस्ट, भारत स्टेज 6 कंप्लायंट थ्री–सिलेंडर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सिक्स–स्पीड, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स प्रदान करती है।

ई–आफिस कार्यप्रणाली लागू होने से आयेगी तेजी

शुभारम्भ

■सीएम ने किया ट्रेड लाइसेंस, सम्पति कर एवं मिश्रित सेवाओं को ऑनलाईन करने हेतु बनाये गये सॉफ्टवेयर का शुभारम्भ

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र बुधवार को ट्रेड लाइसेंस, सम्पति कर एवं मिश्रित सेवाओं को ऑनलाईन करने हेतु बनाये गये सॉफ्टवेयर का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई–आफिस कार्यप्रणाली लागू होने से जहाँ विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी आयेगी एवं गुणात्मक सुधार होगा, वहीं नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किये जाने से पारदर्शिता तथा जवाबदेही में भी वृद्धि होगी। साथ ही नागरिकों को इन सेवाओं की प्राप्ति सुगम, सुलभ एवं घर बैठे प्राप्त हो सकेगी। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी लोगों को यह सुविधा दी जाय। राज्य के निकायों में जो लोग व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, उनका पूरा रिकार्ड रखा जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा विभागीय कामकाज को ई–प्लेटफॉर्म पर लाने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत हैं। राज्य में सचिवालय के कामकाज को ई–ऑफिस से जोडे जाने के पश्चात इस कड़ी में राज्य के शहरी विकास निदेशालय को भी ई–आफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शहरी विकास निदेशालय ई–ऑफिस के रूप में परिवर्तित होने वाला राज्य का पहला निदेशालय है। ई–ऑफिस लागू होने से शहरी विकास निदेशालय की समस्त विभागीय पत्रावलियों को अब डिजिटल प्लेटफार्म पर ई–फाइलिंग के रूप में परिचालित किया जायेगा। एनआईसी एवं आईटीडीए के सहयोग से ई–ऑफिस कार्यप्रणाली को स्थापित किया गया है।

शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने शहरी विकास निदेशालय मे ई–आफिस प्रणालीं लागू किये जाने तथा नागरिक सेवाओं की सरल एवं सुगम पहुँच डिजिटल माध्यम से जनसामान्य तक सुलभ बनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। कौशिक ने कहा कि डिजिटलाईजेशन के फलस्वरूप इन सेवाओं की आपूर्ति प्रणाली में व्यापक सुधार तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही नगर निकायों की सेवाओं के आच्छादन एवं राजस्व में भी व्यापक रूप से बढोत्तरी हो सकेगी।

सचिव, शहरी विकास शैलेश बगौली ने बताया कि नगर निकायों के माध्यम से दी जाने वाली जनआधारित सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने की पहल को नेशनल इन्सट्टियूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भारत सरकार तथा उनकी सहयोगी म–हवअ फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से आरम्भ किया गया है तथा अल्पावधि में ही नगर निकायों की महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाईन किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की गई है। बगौली ने बताया अर्बन रिफार्स एवं ई–गवर्नेस को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से निदेशालय स्तर पर एक सेल के गठन का प्रयास किया जा रहा हैं ताकि अर्बन गवर्नेस को राज्य में बेहतर किया जा सके।

महत्वपूर्ण सेवाओं को भी कर दिया गया आनलाइन

अपर सचिव एवं निदेशक श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि शहरी विकास निदेशालय को पेपरलेस कर डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने का कार्य अत्यंत कम समय मे किया गया है जो राज्य के अन्य विभागों के लिये एक रोल मॉडल सिद्ध होगा। सुमन ने बताया कि ई–ऑफिस हेतु समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है।

शहरी विकास विभाग के द्वारा नगर निकायों के माध्यम से जनसामान्य को दी जाने वाली कतिपय महत्वपूर्ण सेवाओं को भी बुधवार से ऑनलाइन कर दिया गया है। राज्य में अब नगरवासी संपत्ति कर, ट्रेड लाईसेंस एवं अन्य सेवाओं को ई–प्लेटफार्म पर किसी भी स्थान से प्राप्त कर सकेंगे। लोकापर्ण कार्यक्रम में नगर निगम देहरादून के एक व्यवसायी को ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस जारी किया गया जबकि नगर निगम रूडकी के संपत्ति कर के एक आवेदन को ऑनलाइन जमा किया गया। नगर निगम देहरादून के अन्य सेवाओं से संबंधित एक प्रकरण का भी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करते हुए शुल्क की प्राप्ति की गई।

सबसे अधिक प्रवासी पौड़ी व अल्मोड़ा लौटे

विमोचन

■ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का विमोचन

देहरादून। **संवाददाता**

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड लौटे प्रवासियों के संबंध में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए। इसमें विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं को आच्छादित किया गया है। इसके समन्वय के लिए राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी।

आयोग के उपाध्यक्ष डा.एसएस नेगी ने बताया कि 21 जून तक वापस आए प्रवासियों में से 215875 का सर्वेक्षण किया गया। इनमें सबसे अधिक प्रवासी पौड़ी व अल्मोड़ा लौटे हैं। वैसे राज्य के सभी विकाखण्डों में प्रवासी लौटे हैं। इनमें अन्य राज्यों से 80.66 प्रतिशत, विदेशों से 0.29 प्रतिशत, राज्य के भीतर ही एक जनपद से दूसरे जनपद में 18. 11 प्रतिशत और एक जनपद के भीतर ही 1 प्रतिशत हैं।

उत्तराखण्ड लौटे प्रवासियों की स्किल मैपिंग की गई है। इनमें सबसे अधिक 58 प्रतिशत लोग प्राईवेट नौकरी और आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त तकनीकी, बीपीओ, स्वरोजगार से जुड़े लोग हैं। छात्र व मजदूर भी आए हैं।

रिपोर्ट में प्रवासियों के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें तमाम विभागों की योजनाओं को शामिल किया गया है। इसलिए राज्य स्तर पर इनमें समन्वय के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए। उद्यान, कृषि, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री, जैविक कृषि आदि पर विशेष महत्व दिया जाए। रिपेर्ट में कहा गया है कि वापिस लौटे अधिकांश लोग आतिथ्य व सेवा क्षेत्र में अनुभव रखते हैं।

व्यापारियों व उनके स्टाफ का हो कोरोना टेस्ट

संवाददाता देहरादून। व्यापारी वर्ग व उनके स्टाफ का कोविड –19 कोरोना टेस्ट कराये जाने की मांग को लेकर क्रेजी वॉरियर व्यापार मंडल ने मुख्य चिकित्साधिकारी डा. बी एस रमोला से भेंट की और ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही कार्यवाही करने का आग्रह किया। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि दून के प्रमुख बाजार जिसमे पल्टन बाजार , हनुमान चौक ,धामावाला बाजार, दर्शनी गेट, मोती बाजार, झंडा बाजार सब्जी मंडी,तहसील बाजार शामिल है यहा दिन प्रतिदिन कोरोना का सक्रमण व्यापारी वर्ग को अपनी चपेट में ले रहा है और इस बाजार में अत्यधिक भीड़ होने के कारण इस बीमारी के फैलने का खतरा ओर बड रहा है, जिस वजह से व्यापारी वर्ग व ग्राहक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और उनमें भय का माहौल बन चुका है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिंटर्स,74/9,आराघर,देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून
ही मान्य होगा।